हुए इस कपास का विक्रय मूल्य निर्धारित कर सके जिससे किसान इस प्रकार के उत्पीड़िन से मुक्ति पा सकें ।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध मे तत्काल वास्तविकता का पता लगाया जाये और समस्या का निदान निकाला जाये । किसान अनिश्चित वातावरण में अनुकूल प्रतिकूल वातावरण मे कठिन परिश्रम करके अपनी उपज उत्पन्न करता है । उसकी गाढ़ी कमाई का उचित मूल्यांकन हो, यह सरकार उत्तरदायित्व है । इन किसानों को समुचित मूल्य मिलने से कृषि वैज्ञानिकों को भी फसलों की उन्नतिशील जातियों के जनन में प्रोत्साहन मिलेगा । हमारे यहां भी कपास के मूल्य-निर्धारण के लिए एक अधिकारिक संस्था शीघ्र स्थापित हो । इस ओर भी माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये ।

(ix) Reported contamination of rice by fertilisers in F.C.I. godowns at Taran Taran in Punjab.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, नियम 377 के अन्तर्गत मैं इस बहुत ही गंभीर प्रश्न की ओर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

फरवरी, 1976 में भारतीय खाद्य निगम की ओर से 35 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य का चावल पंजाब के तरनतारन गोदाम में रखा गया । चावल के साथ रसायनिक उर्वरक भी उसी गोदाम में रख दिया गया । किसी अधिकारी ने कुछ दिनों के बाद कहा कि खाद और चावल दोनों एक साथ एक ही गोदाम में रखना वैज्ञानिक सिद्धान्तों के विपरीत है । इस चेतावनी को कई बार दोहराया गया और कहा गया कि उर्वरक को तत्काल इस गोदाम से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए क्योंकि उर्वरक से उत्पन्न गर्मी के कारण चावल नष्ट हो जायेगा । इस सब के बावजूद जून, 1979 तक उर्वरक को उक्त गोदाम से नहीं निकाला गया । परिणामस्वरूप चावल पूरी तरह नष्ट हो गया है और वह मनुष्य के खाने योग्य नहीं रह गया है । इस प्रकार की रिपोर्ट चावल की वैज्ञानिक जांच करने के बाद प्राप्त हुई है । किन्तु पंजाब सरकार के अधिकारी अन्यत्र जांच करा कर उसे अच्छा चावल करार देना चाहते है । अतः भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे विषैला चावल लोगों को खाने हेतु न दिया जा सके और अपराधियों को दंडित किया जाए ।

(x) Reported resentment in Kerala against the language policy of the State Government.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, a serious situation prevails in the State of Kerala. There is widespread resentment against the language policy of the Government. The peaceful demonstrators at the Collectorate of Malappuram were subjected to unprovoked firing by the police, killing some and seriously injuring others. The educational institutions in Malappuram, Kozhikode, Trichur and several districts have been closed down.

The deteriorating situation and breakdown of constitutional machinery needs to be examined by the Central Government. I urge upon the Government for a thorough enquiry and statement in the House.

14.07 hrs.

RESOLUTION *RE*. RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

सभापति महोदय : यहां पर रिजोल्यूशन हैं, दोनों एक ही प्रकार के हैं, उन्हें साथ-साथ ही लेते हैं ।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): Sir, I beg to move:

"(i) That this House do resolve that a Parliamentary Committee con-